



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2019/ज्येष्ठ 22, 1941
No. 208]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2019/JYAISTHA 22, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 8 मई, 2019

सं. टीएएमपी/24/2014-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास कांडला भूमि की दर संरचना की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या: टीएएमपी/24/2014-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मार्च, 2019 के 29वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) द्वारा डीपीटी की कांडला भूमि की दर संरचना की वैधता के विस्तार के लिए दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2. डीपीटी की कांडला भूमि के पट्टा किराये पिछली बार 13 नवंबर, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा संशोधित किये गए। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित पट्टा किराये को 01 जनवरी, 2014 से पूर्व व्यापी प्रभाव दिया गया था और पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 31 दिसंबर, 2018 तक की वैधता निर्धारित की गई थी। डीपीटी को हमारे 05 नवंबर, 2018 के पत्र के द्वारा दरों की अधिसूचना में विलंब से बचने के लिए डीपीटी भूमि के किरायों के संशोधन का प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया गया था।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, डीपीटी ने 15 फरवरी 2019 के पत्र के द्वारा उत्तर दिया। डीपीटी ने निम्नलिखित मुद्दे रखे।

- (i) भूमि की दरों और श्रेणीकरण को 'ए', 'एफ1', 'एफ2', 'जी1' 'जी2' में श्रेणीबद्ध करने और 1 जनवरी, 2014 से वर्तमान पट्टाधारकों के पट्टा किरायों में अत्यधिक वृद्धि से संबंधित मुद्दों भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) द्वारा गठित एक समिति द्वारा अध्ययन किया गया है। समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
- (ii) एमओएस ने 16 अक्टूबर, 2018 के पत्र संख्या पीडी-250212/11/2015-वीओसीटी द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी), 2008 के अनुसार पत्तन भूमि के वर्गीकरण/श्रेणीकरण के बारे में स्पष्टीकरण परिपत्र (भूमि प्रबंधन) संख्या 2018 का 1 जारी किया और सूचित किया कि एमओएस के ध्यान में यह लाया गया है कि पत्तन भूमियों का वर्तमान वर्गीकरण और उससे दरमानों का निर्धारण न तो पत्तनों के भीतर और न ही सभी पत्तनों में एक समान है और इससे जटिलतायें और विवाद पैदा होते हैं। इससे पत्तनों की राजस्व वसूली पर प्रभाव पड़ता है। इस मामले पर एमओएस में इसका परीक्षण किया गया और यह निर्णय लिया गया कि पट्टे के प्रयोजन से पत्तन भूमि का वर्गीकरण/श्रेणीकरण एनआईसी, 2008 के अनुसार किया जायेगा। तदनुसार, एमओएस ने सभी महापत्तनों को तदनु रूप कार्रवाई करने का अनुरोध किया। एमओएस से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण को देखते हुए, एनआईसी 2008 के अनुसार पत्तन भूमि के पट्टा श्रेणीकरण/वर्गीकरण के परीक्षण और कार्यान्वयन में कुछ समय लगेगा।
- (iii) इसलिए, कांडला भूमि की दर के संशोधन का प्रस्ताव दायर करने में कुछ समय लगेगा।

3.2. उक्त स्थिति के अनुसार, डीपीटी ने इस प्राधिकरण को मौजूदा दरों की वैधता को 6 महीने के लिए अर्थात् 30 जून, 2019 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख जो भी पहले हो, तक 2% वृद्धि के साथ, विस्तार करने का अनुरोध किया है।

3.3. उक्त स्थिति में, और कि कांडला भूमि की 'ए' से 'जी' श्रेणी की दर संरचना की वैधता 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हो गई है को देखते हुए यह प्राधिकरण कांडला भूमि की 'ए से जी' श्रेणी की मौजूदा दरों की वैधता को 6 महीने के लिए अर्थात् 30 जून, 2019 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख जो भी पहले हो, विस्तार करता है, जैसा डीपीटी ने चाहा है।

4.1. सरकार द्वारा जारी भू-नीति दिशानिर्देश 2014 (जिसके आधार पर डीपीटी की कांडला भूमियों की 'ए से जी' श्रेणियों की दर संरचना नवंबर, 2014 में निर्धारित किये गए थे) अनुबद्ध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये तब तक 2% प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ होंगे जब तक इस प्राधिकरण द्वारा संशोधन नहीं कर दिया जाता। इस प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2014 में अनुमोदित आदेश में भी इस संबंध में यह शर्त विशिष्ट रूप से दी गई है। यह एमओएस द्वारा जारी संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश 2014 में भी दी गई है। चूंकि वर्तमान दर संरचना का जब तक इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं कर दिया जाता तब तक और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 2% की वार्षिक वृद्धि जारी रहेगी और 2% वार्षिक वृद्धि डीपीटी के 'ए से जी' श्रेणियों के लिए कांडला भूमि की दर संरचना में विस्तारित वैधता अवधि में भी लागू रहेगी।

4.2. तथापि, इस संबंध में यह भी नोट किया जाये कि वर्तमान परिदृश्य में निर्वात से बचने के लिए 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्तमान पट्टा किरायों का विस्तार एक अंतरिम व्यवस्था है। इस संबंध में डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर 'ए से जी' श्रेणी के लिए कांडला भूमि के लिए निर्धारित किये जाने वाले पट्टा किरायों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना पड़ेगा, जैसा डीपीटी ने अनुरोध किया है।

5. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से यह प्राधिकरण कांडला भूमि की 'ए से जी' श्रेणी की मौजूदा दरों की वैधता को 6 महीने के लिए अर्थात् 30 जून, 2019 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन-III/4/असा./90/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th May, 2019

No. TAMP/24/2014-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of rate structure of Kandla land of Deendayal Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/24/2014-KPT

Deendayal Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of March 2019)

This case relates to a proposal filed by Deendayal Port Trust (DPT) for extension of the validity of the rate structure for Kandla lands of DPT.

2. The lease rental for the Kandla lands of DPT was last revised by this Authority vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014. The lease rental revised by this Authority was given retrospective effect from 1 January 2014 and validity was prescribed for a period of five years, i.e. up to 31 December 2018. The DPT was requested vide our letter dated 05 November 2018 to expedite filing of its proposal for revision of rentals of DPT land to avoid delay in notification of rates.

3.1. In this backdrop, the DPT, vide its letter dated 15 February 2019 has responded. The response of the DPT brings out the following points:

- (i) The issues related to rates and categorization of land into categories 'A', 'F1', 'F2', 'G1' 'G2', exorbitant increase in lease rentals of existing lessees with effect from 01 January 2014 etc. was studied by a Committee deputed by the Indian Ports Association (IPA). The final Report of the Committee is awaited.
- (ii) The MOS vide letter No.PD-25021/11/2015-VOCT dated 16 October 2018 issued clarification circular (Land Management) No.1 of 2018 on classification / categorization of Port Land as per National Industrial Classification (NIC), 2008 and informed that it has been brought to the notice of the MOS that the present classification on the port lands and the fixation of SOR thereof is not uniform within and across the major ports leading to complications and disputes. This impacts the realization of revenue for the ports. The matter has been examined in the MOS and it has been decided that for the purpose of lease, classification / categorization of Port Land needs to be done as per NIC, 2008. Accordingly, the MOS, has requested all Major Ports to take action accordingly. In view of the above clarifications received from the MOS, the examination and implementation the lease classification / categorization of Port Land as per NIC, 2008 shall take more time.
- (iii) Therefore, filing of proposal for revision of rate of Kandla land will take some time.

3.2. Bringing out the above position, the DPT has requested this Authority to extend the validity of existing rates for 6 months i.e. till 30 June 2019 or till the date of effect of notification of revised lease rentals based on tariff proposal to be filed by DPT, whichever is earlier, with 2% escalation.

3.3. In view of the position brought out above, and since the validity of the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' has expired on 31 December 2018, this Authority extends the validity of the existing rate structure of the Kandla lands for categories 'A to G' from the date of its expiry till 30 June 2019 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier as sought by DPT.

4.1. The Land Policy Guidelines of 2014 issued by the Government (based on which the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT has been fixed in November 2014) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order approved by this Authority in November 2014 also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the amended Land Policy Guidelines, 2014 issued by the MOS. Since the existing Rate structure already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by the Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT.

4.2. However, it is to be noted in this regard that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Kandla lands for categories 'A to G' based on a proposal filed by the DPT in this regard will have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

5. In the result, and for the reasons given above, this Authority extends the validity of the existing rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT from the date of its expiry till 30 June 2019 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./90/19]